सत्र-04 05 जनवरी, 2026

खण्ड- 08 .... सोमवार, ...

अंक- 18 15 पौष,1947(शक्)

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्यमेव जयते

आठवीं विधान सभा

चौथा सत्र

अधिकृत विवरण

(खण्ड-08 सत्र-04 में अंक 18 से 22 तक सम्मिलित हैं।)

दिल्ली विभान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

रंजीत सिंह

सचिव

RANJEET SINGH

Secretary

महेन्द्र गुप्ता

उप सचिव (सम्पादन)

MAHENDRA GUPTA

Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-4 सोमवार, 05 जनवरी, 2026/15 पौष,1947(शक्)अंक-18

दिल्ली विधान सभा

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ सं.
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	4-5
2.	सदन में अव्यवस्था	6
3.	माननीय उपराज्यपाल का अभिभाषण	7-20
4.	निधन संबंधी उल्लेख	21-23
5.	माननीय उपराज्यपाल के अभिभाषण की हिंदी एवं अंग्रेजी प्रति	24-48
6.	सदस्यों का निलंबन सबंधी प्रस्ताव	49

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सत्र-4 सोमवार, 05 जनवरी, 2026/15 पौष,1947(शक्)अंक-18

निम्नलिखित सदस्य सदन में उपस्थित हुए:

क्र.सं.	सदस्य का नाम	क्र.सं.	सदस्य का नाम
1-	श्री अहिर दीपक चौधरी	36-	श्री प्रद्यूम्न सिंह राजपूत
2-	श्री अभय कुमार वर्मा	37-	श्री प्रवेश साहिब सिंह
3-	डॉ अजय दत्त	38-	श्री पवन शर्मा
4-	श्री अजय कुमार महावर	39-	श्रीमती पूनम शर्मा
5-	श्री अनिल झा	40-	श्री प्रवेश रत्न
6-	श्री अनिल कुमार शर्मा	41-	श्री प्रेम चौहान
7-	श्री अरविन्दर सिंह लवली	42-	श्री पुनरदीप सिंह साहनी
8-	श्री आशीष सूद	43-	श्री राज करन खत्री
9-	श्री अशोक गोयल	44-	श्री राज कुमार भाटिया
10-	श्री चन्दन कुमार चौधरी	45-	श्री राज कुमार चौहान
11-	चौधरी जुबैर अहमद	46-	श्री राम सिंह नेताजी
12-	डॉ. अनिल गोयल	47-	श्री रवि कान्त
13-	श्री गजेन्द्र दराल	48-	श्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह
14-	श्री गजेन्द्र सिंह यादव	49-	श्री रविन्दर सिंह नेगी
15-	श्री गोपाल राय	50-	श्रीमती रेखा गुप्ता
16-	श्री हरीशे खुराना	51-	श्री सही राम

17-	श्री इमरान हुसैन	52-	श्री संदीप सहरावत
18-	श्री जरनैल सिंह	53-	श्री संजय गोयल
19-	श्री जितेन्द्र महाजन	54-	श्री संजीव झा
20-	श्री कैलाश गहलोत	55-	श्री सतीश उपाध्याय
21-	श्री कैलाश गंगवाल	56-	श्री श्याम शर्मा
22-	श्री कपिल मिश्रा	57-	श्री सोम दत्त
23-	श्री करनैल सिंह	58-	श्री सुरेन्द्र कुमार
24-	श्री करतार सिंह तंवर	59-	श्री सूर्य प्रकाश खत्री
25-	श्री कुलदीप कुमार	60	श्री तरविन्दर सिंह मारवाह
26-	श्री कुलदीप सोलंकी	61	श्री तिलक राम गुप्ता
27-	श्री कुलवन्त राणा	62	श्री उमंग बजाज
28-	श्री मनजिंदर सिंह सिरसा	63	श्री वीर सिंह धिंगान
29-	श्री मनोज कुमार द्वौकीन	64	श्री विजेन्द्र गुप्ता
30-	श्री मोहन सिंह बिष्ट	65	श्री वीरेन्द्र सिंह कादियान
31-	श्री मुकेश कुमार अहलावत	66	श्री विशेष रवि
32-	श्रीमती नीलम पहलवान		
33-	श्री नीरज बैसोया		
34-	श्री ओम प्रकाश शर्मा		
35-	श्री पंकज कुमार सिंह		

दिल्ली विधान सभा

की

कार्यवाही

सोमवार, 05 जनवरी 2026/15 पौष, 1947(शक)

सदन पूर्वाह्न 11.02 बजे समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष श्री विजेन्द्र गुप्ता पीठासीन हुए।

राष्ट्रगान

भारत माता की जय

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य गण, आज हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि माननीय उपराज्यपाल महोदय श्री विनय कुमार सक्सेना जी सदन में अभिभाषण के लिए आए हैं। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय उपराज्यपाल महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो सदन को संबोधित करें।

माननीय उपराज्यपाल: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्य गण,

...व्यवधान...

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: मार्शल्स, संजीव जी को बाहर ले जाए। संजीव जी को बाहर, संजीव झा जी को बाहर ले जाइये।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री संजीव झा को सदन से बाहर किया गया)

माननीय उपराज्यपाल: मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियां और कुछ नई नीतियों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो दिल्ली के नागरिकों को उनके लक्ष्यों और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में, कार्यान्वित की जा रही हैं।

...व्यवधान..

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कुलदीप कुमार को बाहर ले जायें। कुलदीप कुमार को बाहर ले। सोमदत जी को बाहर ले जाएं।

...व्यवधान...

सोम दत जी को बाहर ले जायें। कुलदीप कुमार जी को बाहर ले जायें।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार और श्री सोम दत्त को सदन से बाहर किया गया)

माननीय उपराज्यपाल: विशाल जन आदेश द्वारा दिल्ली की जनता ने मेरी सरकार उनके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर विश्वास व्यक्त किया है।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: सुरेन्द्र कुमार जी को बाहर ले जायें।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्र कुमार को सदन से बाहर किया गया)

माननीय उपराज्यपाल: मेरी सरकार इस जनादेश में समाहित अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन के लिए कृत संकल्प है। मेरी सरकार के सम्मुख सबसे बड़ी चुनौती शासन और प्रशासन में वर्षों से व्याप्त जड़ता तथा नकारात्मकता से निपटने की थी। लगभग 10 महीनों के अल्पकाल में।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जरनैल सिंह को बाहर ले जाइए।

(माननीय अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार मार्शल्स द्वारा माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह को सदन से बाहर किया गया)

माननीय उपराज्यपाल: मेरी सरकार ने इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

महात्मा गांधी के सर्वोदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 10 महीनों में मेरी सरकार ने दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण की दिशा में अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए जिनका क्रियान्वयन जारी है।

माननीय सदस्यगण, इस वर्ष सरकार ने ₹1 लाख करोड़ रुपए का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया जो सभी 10 प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी तथा सामाजिक न्याय हैं।

सरकार ने ease of doing business के तहत व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है तथा निवेश आकर्षित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किए हैं। इसमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार आदि प्रमुख हैं।

उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए ई गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज को सिटीजन सर्विस सेंटर्स (CSCs) के साथ सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण करने के पांच महीने के भीतर प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए सभी सरकारी कार्यालयों में ई ऑफिस का क्रियान्वयन किया गया है जोकि काफ़ी समय से लंबित था।

इसी प्रकार ease of doing business की पहल के तहत शराब की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को 24X7 खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से व्यापारियों को अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से राहत मिलेगी। इसी के साथ दिल्ली दुकानों एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में अन्य संशोधन के लिए भी एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र, भू उपयोग, परिवर्तन, फैक्ट्री और व्यापार, लाइसेंस आदि को प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। 29 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित कर उन्हें चार व्यापक लेबर कोर्ट्स में एकीकृत करते हुए सरकार ने केंद्र सरकार के साथ संपूर्ण समन्वय में आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से ना केवल कानूनों की जटिलता को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियां और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी ठोस प्रयास किए गए हैं। बहुत ही कम समय में इन सुधारों को लागू करने के लिए मैं मुख्यमंत्री महोदया के नेतृत्व वाली सरकार का साधुवाद करता हूं।

यह सुनिश्चित करने के लिए विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुंचे, सरकार ने 'जिला परियोजना' निधि योजना की शुरुआत की है। 1400/- करोड़ रूपये की राशि के साथ मुख्यमंत्री

विकास निधि को पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय सदस्य गण

मेरी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए अपने कुल व्यय का 13% आवंटित किया है। जो अन्य राज्यों द्वारा स्वास्थ्य पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 17 अस्पतालों में विभिन्न निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सितंबर 2025 में पांच अस्पताल ब्लॉकों का उद्घाटन किया गया। फरवरी 2025 में नई सरकार के गठन के पश्चात स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया गया पहला बड़ा निर्णय 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' को लागू करना रहा। अब तक 6,72,551 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2,62,383 वय वंदना योजना कार्ड शामिल है। योजना के अंतर्गत दिल्ली में 188 अस्पताल- जिसमें 137 निजी एवं 51 सरकारी- empanel किए गए हैं। इसके तहत अब तक 19,287 मरीजों का सफल उपचार किया गया है।

PM-ABHIM योजना के अंतर्गत 238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सदृढ़ हुई है और बड़े अस्पतालों पर भार कम हुआ है। किफायती दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 29 जन औषधि केंद्र भी कार्यरत है। इसके अतिरिक्त 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं तथा नौ क्रिटिकल केयर ब्लॉक स्थापित किए जाने की योजना पर कार्य जारी है।

डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत 37 अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम को लागू किया गया है।

एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने तथा 'दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी' के गठन को स्वीकृति प्रदान की है। इससे आयुष चिकित्सा पद्धति का समग्र विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को और सुदृढ करते हुए 53 नई एंबुलेंस जोड़ी गई है। जिससे एंबुलेंस की कुल संख्या अब 330 हो गई है।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम तथा पीपीपी डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को निशुल्क तथा सामान्य नागरिकों को किफायती हीमो-डायलिसिस सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में 16 डायलिसिस केंद्रों में 300 मशीनें कार्यरत हैं। जिसमें मेरी सरकार ने बहुत ही कम समय में ही 150 मशीनें लगवाई हैं। पिछले कुछ महीनों में 926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरामेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन टीचिंग विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में रोगी सेवा और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने नर्सिंग इंटर्न के stipend को 500/-रूपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 13150/- रूपये प्रतिमाह कर दिया है। सरकार का यह कदम प्रशंसनीय है।

इसके साथ ही मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए द्वारका में दिल्ली का पहला ब्रेन हेल्थ क्लीनिक भी प्रारंभ किया गया है।

माननीय सदस्यगण

मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ वर्ष 2025-26 में शिक्षा के क्षेत्र में कुल बजट का 19% आवंटन किया गया है। यह आवंटन दर्शाता है कि सरकार शिक्षा को भविष्य में सकारात्मक निवेश के रूप में देखती है।

निजी विद्यालयों द्वारा मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए 'दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पादर्शिता) अधिनियम, 2025' पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से रोकने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

जनता के राष्ट्रपति डॉ. एपीजे कलाम की स्मृति और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में 100 डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाओं की स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में अत्याधुनिक तकनीक और एआई का उपयोग कर अंग्रेजी, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएं एवं फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं का शिक्षण भी कराया जाएगा।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत पीएम श्री विद्यालयों की अवधारणा से प्रेरित होकर दिल्ली में 75 सीएम श्री विद्यालयों की शुरुआत की गई है। इन विद्यालयों में प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालायें, पुस्तकालय आदि की सुविधाएं होंगी।

कक्षा नौवीं से 12वीं तक के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना की जा रही है। आज के डिजिटल युग में तकनीक तक पहुंच कोई विलासता नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत कक्षा दसवीं से 11वीं में प्रवेश लेने वाले 1200 मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क लैपटॉप प्रदान किए जाने की योजना पर कार्य जारी है।

सीबीएससी द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए सरकारी विद्यालयों में 175 आईटी लैब्स की स्थापना की जा रही है। जिसमें प्रत्येक प्रयोगशाला में 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे।

मेरी सरकार ने खिलाड़ियों के लिए खेल प्रोत्साहन राशि को दुगना से ज्यादा बढ़ाकर सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत ओलंपिक तथा पैरा ओलंपिक में खेलों में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक विजेताओं को क्रमश: 7 करोड़, पांच करोड़ और तीन करोड़ रूपये की पुरस्कार राशि देने का निर्णय लिया गया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त एशियाई कॉमनवेल्थ व अन्य अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्रीय खेलों में भी खेल प्रोत्साहित राशि को डेढ़ से तीन गुना तक बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाड़ियों के लिए सरकार के समर्पण को मैं साधुवाद देता हूं।

माननीय सदस्य गण

मेरी सरकार ने वर्ष 2025-26 के बजट में कैपिटल एक्सपेंडिचर को दो गुना करते हुए लगभग 28000 करोड़ रूपये किया है। इसका उद्देश्य केवल ढांचा का निर्माण करना नहीं बल्कि दिल्ली को भविष्य के लिए एक ऐसी राजधानी के रूप में तैयार करना है जो गति सुविधा और स्थिरता का संतुलन प्रस्तुत करे।

इलेक्ट्रॉनिक वाहन पहल के अन्तर्गत भारत सरकार के सहयोग से लगभग 3, 535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल है। जिनमें लगभग 1150 देवी बसें लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए चलाई जा रही है। इसके साथ ही 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स की स्थापना की योजना पर भी कार्य जारी है।

सरकार बसों और मेट्रो के बीच सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) लागू करने की योजना पर कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को यह सुविधा निशुल्क पिंक कार्ड के रूप में प्रदान की जाएगी।

सरकार ने सार्वजनिक परिवन को बढ़ावा देने के लिए मेट्रो फेस फोर के लिए लगभग 3,300 करोड़ रूपये का प्रावधान किया है। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, 'दिल्ली मेरठ नमो भारत रेल सेवा' शुरू कर दी गई है जिसके लिए सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है।

मेरी सरकार ने थोड़े ही समय के कार्यकाल में 150 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण किया है एवं 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण और पुनर्विकास मार्च 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 600 किलोमीटर सडकों का नवीनीकरण वर्ष 2026 में नियोजित है मेरी सरकार संकल्पकृत है कि बची हुई 300 किलोमीटर सड़कें भी वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक पूरी तरह से नवीनीकृत कर ली जाएं।

कई वर्षों के बाद सरकार को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से 803 करोड़ रूपये की केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली की तीन प्रमुख सड़कों - एमजी रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड- के विकास की योजना पर कार्य चल रहा है।

मेरी सरकार द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड टू के निर्माण के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रूपये की लागत से बनी ये परिवर्तनकारी परियोजनाएं दिल्ली में यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएंगी और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में संपर्क व्यवस्था को सुदृढ करेंगी।

काफी समय से लंबित नंद नगरी फ्लाई ओवर का कार्य भी मेरी सरकार ने काफी कम समय में पूर्ण किया है जिससे ट्रांस यमुना के क्षेत्र अनेक कालोनियों का दिल्ली और एनसीआर से बेहतर संपर्क संभव हो सका है। बारापुला फ्लाई ओवर को पूर्ण करने का कार्य जो वर्षों से लंबित था, दोबारा शुरू किया गया है एवं अब सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त करने के बाद मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसी प्रकार मोदी मिल और सावित्री सिनेमा पर नए फ्लाई ओवरों का निर्माण भी स्वीकृत किया गया है।

जलभराव दिल्ली की एक दीर्घकालीक समस्या रही है, विशेषकर मानसून के दौरान। इस दिशा में सरकार ने सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए है। युद्धस्तर पर नालों की गाद निकासी की गई है और अब तक लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद हटाई गई है। सीवर लाइनों की नियमित सफाई की जा रही है तथा संवेदनशील क्षेत्रों में जलभराव की समस्या को रोकने के लिए रियलटाइम मॉनिटरिंग युक्त स्मार्ट ड्रेनेज सिस्टम विकसित किया जा रहा है।

लगभग 50 वर्षों के बाद पूरे दिल्ली के लिए एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है जिसे आने वाले वर्षों में 56000 करोड़ रुपए की लागत से लागू किया जाएगा।

केंद्र द्वारा पारित तीनों आपराधिक कानूनों को दिल्ली में भी सुचारू रूप से लागू किया गया है। न्यायालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने तथा फैमिली कोर्ट, आवासीय भवन अधिवक्ता कक्ष और नए न्यायालय परिसरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए परियोजनाएं प्रारंभ की गई है। नरेला में उच्च सुरक्षा जेल परिसर के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की जा रही है। ई फोरेंसिक सिस्टम लागू कर दिया गया है जो सरकार की न्याय के प्रति प्राथमिकता को दर्शाता है।

झुग्गी वासियों को सतत और समग्र विकास के लिए मेरी सरकार का कृतसंकल्प है। पिछली सरकार के समय के बने जजर हो चुके ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के नवीनीकरण का कार्य कराकर सरकार द्वारा गरीब परिवारों को घर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही इन कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए लगभग 700 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। इन कॉलोनियों में आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन की सुविधा भी दी जा रही है। सामाजिक कल्याण के प्रति अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत मेरी सरकार ने अटल कैंटीन योजना प्रारंभ की है जिसके अंतर्गत मात्र 5 रुपये में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर संकल्पित 100 में से 45 अटल कैंटीन का शुभारंभ किया गया है तथा शेष कैंटीनने भी शीघ्र ही प्रारंभ की जाएगी। गरीब परिवारों की सुविधाओं और सम्मान के लिए माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के इस कदम का मैं स्वागत करता हूं।

माननीय सदस्य गण,

वर्षों की उपेक्षा और प्रदूषण के कारण यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही यमुना की स्वच्छता और को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, यमुना rejuvenation हेतु कई स्तर पर एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए एसटीपी लगाए जा रहे हैं और वर्तमान एसटीपीस के अपग्रेडेशन

के कार्य प्राथमिकता के साथ किये जा रहे हैं। इन सभी पहलों का प्रभाव आने वाले समय में दिखाई देगा। ऐसे सारे नाले जो यमुना को प्रदूषित करते हैं उन्हें टैप करके ट्रीट करने के लिए डीसेंट्रलाइज एसटीपीज लगाने की योजना पर भी सरकार कार्यरत है।

दिल्ली जल बोर्ड को जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ₹9000 करोड़ का आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ करने के उद्देश्य से वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के रिसाइक्लिंग को भी प्रोत्साहित कर रही है और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रेनों की सिल्ट सफाई और इनमें गिरने वाले गोबर की रोकथाम के लिए बायोगैस प्लांट लगाने के कार्य भी प्रारंभ किए गए हैं।

नवंबर 2025 में सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया जिनके कारण दिल्ली नगर निगम द्वारा अनाधिकृत निर्माण के लिए बुक की गई संपत्तियों को बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद अब बिजली वितरण कंपनियां केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इंकार नहीं कर सकती या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकती कि कोई संपत्ति नगर निगम की बुक की हुई सूची में शामिल है। इस नीति परिवर्तन से दिल्ली के 1 लाख 25000 से अधिक परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर पहले इन प्रतिबंधों के कारण बिजली सुविधा से वंचित थे और अब वैध रूप से बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय सदस्यगण,

दिल्ली में वर्षों से लंबित पीएम स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण एवं अभिलेख संचालन नियम, 2025 अधिसूचित किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में लालडोरा आबादी को पहली बार संपत्ति के वैधानिक अधिकार प्राप्त होंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए मेरी सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने और नागरिक सेवाओं तक जनता की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली सरकार ने 'सुशासन दिवस' 25 दिसम्बर, 2025 से अपने 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन कर 13 नए जिले बनाए हैं ताकि एमसीडी जोन, एनडीएमसी और दिल्ली कैंट

के साथ सीमाएं समन्वित हो सकें। जनहित के लिए किए गए इस प्रशासनिक सुधार के लिए सरकार प्रशंसा की पात्र है।

इसके साथ ही सभी 13 जिलों में मिनी सचिवालयों की स्थापना को मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। ये बहु विभागीय केंद्र एक ही भवन में सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे और नागरिकों के लिए एकल संपर्क बिंदु के रूप में कार्य करेंगे।

एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत साप्ताहिक जन सुनवाई के माध्यम से मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उपजिलाधिकारी सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनकर उनके त्वरित समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।

जनता की शिकायतों के समयबद्ध निवारण, प्रभावी सेवा वितरण, सूचनाओं के व्यापक प्रसार तथा नागरिकों के सुझावों और विचारों को प्राप्त करने के उद्देश्य से 'दिल्ली मित्र ऐप' की परिकल्पना की गई है। जन शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए वेब पोर्टल डेवलपमेंट का कार्य भी जारी है।

इसके साथ ही 'विकसित दिल्ली इंटर्नशिप कार्यक्रम' के अंतर्गत 85 युवाओं को जोड़ा गया है। पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप कार्यक्रम को भी स्वीकृति प्रदान की है।

आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में सह स्थापित (को-लोकेशन) तथा सरकारी विद्यालयों के साथ मैप भी किया गया है। 502 आंगनबाड़ी सह शिशुगृह- 'पालना' भी शुरू किए गए हैं। महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने प्रतिबंधों को हटाते हुए उन्हें दिल्ली में नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है।

समाज के वंचित वर्गों के कल्याण हेतु पश्चिम बिहार में सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक ग्रह, तिमारपुर में अटल दृष्टि ग्रह तथा नरेला में अटल आशागृह की स्थापना कर इन्हें आम जन के लिए खोल दिया गया है।

इसके अतिरिक्त GRAP के दौरान दिल्ली एनसीआर में निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर निर्माण श्रमिकों के हित की रक्षा करते हुए भवन निर्माण अन्य निर्माण श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। इस क्रम में प्रत्येक योग्य श्रमिक को 10 हजार

रुपए की अनुग्रह राशि वितरित की गई है जिससे कठिन समय में उनकी आजीविका को सहारा मिल सके।

दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को सरकार ने पुनर्जीवित किया जिसके तहत लगभग 1715 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 776 विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जाएगा।

व्यापक देखभाल की आवश्यकता वाले दिव्यांगजनों को अन्य पेंशनों के अतिरिक्त प्रतिमाह ₹6000 की सहायता की भी मंजूरी दी गई है। जिससे देखभाल कर्ताओं की व्यवस्था, उपचार तथा सहायक उपकरणों की लागत को पूरा करने में मदद मिलेगी।

1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी हेतु सरकार ने एक नई नीति को मंजूरी दी है और अब तक 56 लाभार्थियों को नौकरियां प्रदान की गई हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में रह रहें जम्मू कश्मीर प्रवासियों को एक मुश्त राहत प्रदान करते हुए आय की शर्त को समाप्त कर दी गई हैं।

देश की राजधानी होने के नाते तथा एकता और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सरकार ने भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के 'स्थापना दिवस' मनाना प्रारंभ किया है। इसके अतिरिक्त पर्यटन विभाग द्वारा अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आम महोत्सव और तीज महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण दिवसों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में आम जनता की सहभागिता अत्यंत उत्साहजनक और सराहनीय रही है।

पहली बार कावड़ समितियों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से सीधे डीबीटी के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप इस वर्ष आयोजित कावड़ यात्रा अत्यंत सफल रही। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से तथा आयोजन समितियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए सरकार ने रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को 1200 यूनिट तक नि:शुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। यमुना के घाटों पर इस वर्ष बेहतरीन तरीके से छठ महापर्व एवं दीपोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह गुरु तेग बहादुर जी का 350वां बलिदान दिवस और वीर बाल दिवस भी मनाया गया।

मेरी सरकार का यह दृढ़ विश्वास है कि सभी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए नागरिकों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना ही समावेशी और संवेदनशील शासन की पहचान है।

माननीय सदस्यगण,

वायु प्रदूषण आज हमारे शहर के सामने सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है।

प्रदूषण नियंत्रण पर मेरी सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय सरकार ने जून, 2025 में ही एक व्यापक वर्ष भर लागू होने वाली और समयबद्ध वायु प्रदूषण न्यूनीकरण योजना आरंभ की है। यह योजना रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े परिवर्तन/प्रवर्तन तथा जनभागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के समन्वित प्रयास शामिल हैं।

वायु गुणवत्ता की निगरानी को सुदृढ़ करने हेतु छह नए एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। इससे रियल टाइम डाटा की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी। प्रभावी उपायों को अपनाकर विकास विभाग ने 2025 की सर्दियों में दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को शून्य कर दिया है।

इसके अलावा हर वर्ष लगभग 2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की तकनीक-आधारित फिटनेस जांच के लिए नंद नगरी, बुराड़ी और तेहखंड में तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन (ATS) स्थापित करने का कार्य त्वरित गति से किया जा रहा है।

हाल के सप्ताहों में प्रदूषण स्तर बढ़ने पर सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक दिन रात कार्यरत निरीक्षण टीमें तैनात की गईं। 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत हरित आवरण का विस्तार किया जा रहा है। केवल 10 महीनों में ही 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर non-polluting public transport को सशक्त किया गया है। कई रूट्स पर इंटरस्टेट इ.वी. बसों की भी शुरुआत की गई है। धूल नियंत्रण के लिए डबल शिफ्ट में मैकेनिकल रोड स्वीपर्स, जल छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। सैनिटेशन व्यवस्था सुदृढ़ करने एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से एमसीडी को 10 वर्षों के लिए 70 एमआरएसएम और 1000

लीटर पिकर मशीनंस के लिए 2300 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करने का सराहनीय निर्णय लिया गया है।

शीत ऋतु में खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु आरडब्ल्यूएस को 3000 इलेक्ट्रिक हीटर निशु:ल्क वितरित किए गए हैं और शहर में 24X7 निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की गई है।

मेरी सरकार ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को इस वर्ष 500 करोड़ रूपये का अतिरिक्त अनुदान दिया है तथा आगे प्रतिवर्ष 300 करोड़ रूपये का अनुदान दिया जाएगा, जो कि कूड़ा निस्तारण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में तेजी लाएगा।

दिल्ली सरकार पीपीपी मॉडल के तहत होलम्बी कलां में दिल्ली का पहला एकीकृत ई-वेस्ट इको पार्क स्थापित करने की दिशा में कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप प्रतिवर्ष 51000 टन से अधिक ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा।

सरकार बॉयोमाइनिंग और वेस्ट-टू- एनर्जी तकनीकों से गाजीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल को साफ कर रही है। 2027 तक की समय सीमा के तहत ट्रोमेल मशीनों और पीपीपी मॉडल के तहत कचरे के पहाड़ों पर जमा कूड़ा हटाकर दिल्ली को कचरा मुक्त बनाने का लक्ष्य है।

वाहन प्रदूषण नियंत्रण भी सरकार का एक प्रमुख फोकस एरिया है। इलेक्ट्रिक बसों , लास्ट-माइल ई-मोबिलिटी और तेजी से विस्तार किए जा रहे ईवी चार्जिंग नेटवर्क के माध्यम से दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली निरंतर मजबूत हो रही है। दिसंबर, 2026 तक संशोधित ई.वी. नीति के तहत बसों के बेड़े में 7700 से अधिक स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। यातायात जाम और उससे होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने 600 अतिरिक्त कर्मी लगाए हैं।

सी. एण्ड डी. मलबा जो वर्तमान में लगभग 6000 टन प्रतिदिन है के व्यवस्थित निस्तारण के लिए चार प्रोसेसिंग प्लांट पहले से कार्यरत हैं तथा 1000 टीपीडी क्षमता का एक नया प्लांट दिसंबर, 2026 तक चालू किया जाएगा। इसके साथ ही सरकारी परियोजनाओं में प्रोसेस्ड कचरे के अनिवार्य पुन: उपयोग के माध्यम से सर्कुलर इकॉनमी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सड़क धूल नियंत्रण को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी श्रेणियों की सड़कों को शामिल करते हुए एक व्यापक सड़क पूनर्विकास एवं ग्रीनिंग योजना तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर

यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव प्रणालियों के साथ अगले शीतकाल से पहले पूरी तरह लागू किया जाएगा।

औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्य को नियमित निरीक्षण तथा वास्तविक समय निगरानी और अवैध इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से मजबूत किया गया है। केवल स्वच्छ उद्योगों को अनुमति देने के लिए नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है।

इन प्रयासों को और मजबूती देने के लिए कई पहल किए गए हैं। इनमें ऊंची व्यासायिक इमारतों पर एंटी-स्मॉग प्रणालियों की अनिवार्यता, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट-स्प्रे सिस्टम की स्थापना तथा "नो पीयूसीसी नो फ्यूल" नीति का सख्त प्रवर्तन शामिल है। इसके अतिरिक्त सड़कों पर पीडब्ल्यूडी, डीडीए, एनडीएमसी एंड डीएमआरसी द्वारा अब तक 650 से अधिक मिस्ट -स्प्रे सिस्टम लगा दिए गए हैं।

स्वच्छ वायु एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार के प्रयास तभी सफल हो सकते हैं जब नागरिकों का सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। विद्यालयों, आरडब्ल्यूएस और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से जन-जागरूकता और सहभागिता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही दिल्ली को हरित शहर बनाने की प्रतिबद्धता के तहत अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इस दिशा में आगामी चार वर्षों में लगभग 35 लाख वृक्ष तथा 63 लाख झाड़ियां लगाई जाएंगी।: इसके साथ ही स्वदेशी पेड़ जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल आदि के वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। सोलराइजेशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पीएम सूर्य घर योजना के तहत स्टेट सब्सिडी को 2000 रुपये प्रति किलोवाट को बढ़ाकर 10,000 हजार रुपये प्रति किलोवाट कर दिया है।

माननीय सदस्यगण,

यद्यपि सरकार ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं, फिर भी कई चुनौतियों पर पार पाना बाकी है। सरकार सभी चुनौतियों का सामना पूर्ण दृढ़ता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रही है तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि सामूहिक प्रयासों से इन बाधाओं को अवसरों में परिवर्तित किया जा सकता है।

मैंने आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि

सभी माननीय सदस्य जनहित को सर्वोपरि रखते हुए सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनेंगे तथा इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को अक्षुण बनाए रखेंगे।

माननीय सदस्यगण,

जन प्रतिनिधियों का ये संवैधानिक दायित्व है कि वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को सकारात्मक नेतृत्व और सार्थक दिशा प्रदान करें। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण तथा शासन की प्रतिक्रियाओं को दिशा देने में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जनता की आशाओं को ठोस परिणामों और समावेशी विकास में रूपांतरित कर सकेंगे।

मेरी यह आशा और अपेक्षा है कि इस सम्मानित सदन की कार्यवाहियां, परिपक्वता, विवेक, सहयोग तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की भावना के साथ संपन्न होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि निस्वार्थ सेवा की भावना और जनता के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर इस सदन की कार्यवाही दिल्ली के समग्र विकास और प्रगति में सार्थक योगदान देगी।

इन शब्दों के साथ मैं आप सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख- समृद्धि की कामना करता हूं।

जय हिंद।

(राष्ट्रगान)

माननीय अध्यक्ष : सदन की बैठक 30 मिनट बाद आरंभ होगी।

सदन अपराहन 12.16 बजे पुनः समवेत हुआ।

माननीय अध्यक्ष (श्री विजेंद्र गुप्ता) पीठासीन हुये।

(राष्ट्रीय गीत- वन्दे मातरम)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, आठवीं विधानसभा के चौथे सत्र में आप सबका स्वागत है। आप सबको नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनायें। नया साल आप सबके लिये सामाजिक और राजनीतिक जीवन में सार्थक सिद्ध हो ऐसी मेरी कामना है। मेरा सभी माननीय

सदस्यों से अनुरोध है कि वे शालीनतापूर्वक अपने विचार सदन में प्रस्तुत करें और सदन का समय खराब ना होने दें, साथ ही कार्यसूची में सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी भी अन्य विषय को मेरी अनुमति के बिना ना उठायें।

मुझे आशा है कि आप सदन की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलाने में मुझे सहयोग देंगे।

निधन संबंधी उल्लेख

अब हमारे बीच में पूर्व विधायक **श्री राजेश गहलौत के निधन के प्रति शोक संवेदना।** माननीय सदस्यगण जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 14 अगस्त, 2025 को दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री राजेश गहलौत जी का निधन हो गया, वे 60 वर्ष के थे। वे मटियाला विधानसभा क्षेत्र से पांचवीं विधानसभा के सदस्य चुने गये थे। राजनीति तथा समाज सेवा में उनकी खास रूचि थी तथा अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिये वे हमेशा समर्पित रहे। मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री राजेश गहलौत जी को श्रंद्धाजली देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवारजनों को इस अपार दु:ख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

स्वर्गीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी के निधन के प्रति शोक संवेदना।

माननीय सदस्यगण, आप सबको ज्ञात होगा कि दिल्ली के वरिष्ट राजनेता पूर्व सांसद तथा दिल्ली विधानसभा के नेता, प्रतिपक्ष रहे श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी का गत 30 सितम्बर, 2025 को 93वे वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके निधन से देश और दिल्ली की राजनीति ने एक महान, अनुभवी और जनसेवा के लिये समर्पित व्यक्तित्व को खो दिया है। श्री मल्होत्रा जी 36 वर्षों तक दिल्ली के डीएवी कॉलेज में प्रोफेसर रहे। वे वर्ष 1958 से 1968 तक दो बार दिल्ली नगर निगम के सदस्य निर्वाचित हुये। वे वर्ष 1968 से 72 तक दिल्ली प्रशासन के मुख्य कार्यकारी पार्षद रहे और वर्ष 1972 से 1977 तक दिल्ली महानगर परिषद में प्रतिपक्ष के नेता रहे।

वे छठी, नौवीं, 13वीं और 14वीं लोकसभा के सदस्य रहे और वर्ष 1994 में राज्यसभा के सदस्य भी चुने गए। सांसद रहते हुए उन्होंने 26 से भी अधिक महत्वपूर्ण संसदीय समितियों के सभापति और सदस्य के रूप में कार्य किया। वे वर्ष 2008 में ग्रेटर कैलाश क्षेत्र से चौथी दिल्ली विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा नेता, प्रतिपक्ष रहे।

वे कई खेल परिषदों और खेल संघों के अध्यक्ष रहे और भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष रहे। उन्होंने अनेक एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता की।

उनका पूरा जीवन आम जनता और उपेक्षित वर्गों के हित के लिए समर्पित रहा जिस कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा।

श्री मल्होत्रा जी ने अपने सार्वजनिक जीवन में संसदीय गरिमा, लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के मूल्यों को हमेशा प्राथमिकता दी। पार्षद, विधायक तथा सांसद के रूप में और नेता, प्रतिपक्ष के रूप में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उन्होंने रचनात्मक संवाद की परंपरा को मजबूती प्रदान की। उनका जीवन सादगी, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का बहुत बड़ा उदाहरण रहा है। उनके निधन से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति हुई है।

मैं अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी को श्रद्धांजलि देता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

श्री विनय शर्मा पूर्व विधायक के निधन के प्रति शोक संवेदना :

माननीय सदस्यगण जैसा कि आप सबको विदित है कि दिनांक 26 दिसंबर 2025 को दिल्ली विधानसभा के पूर्व विधायक श्री विनय शर्मा जी का निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। वे बाबरपुर क्षेत्र से तीसरी विधानसभा के सदस्य चुने गए थे। सामाजिक कार्य में उनकी गहन रुचि थी तथा सदन में उन्होंने जनहित से जुडे मुद्दों को लगातार उठाया। मैं अपनी ओर से और पूरे सदन की ओर से स्वर्गीय श्री विनय शर्मा जी को श्रद्धांजलि देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट के कारण मृतक नागरिकों के प्रति शोक संवेदना :

माननीय सदस्यगण ।जैसा कि आपको विदित है कि गत 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले की नजदीक हुए भीषण कार ब्लास्ट में 15 निर्दोष नागरिकों की दुखद मौत हो गई तथा 20 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस अमानवीय और कायरतापूर्ण कृत्य से ना केवल पीड़ित परिवारों के लिए अपूर्णीय क्षति हुई है बल्कि समाज की शांति, सौहार्द और लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आघात पहुंचा है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। मैं अपनी

ओर से तथा पूरे सदन की ओर से जान गंवाने वाले सभी नागरिकों को श्रद्धांजलि देता हूँ तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ को भी की भी कामना करता हूँ। अब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया जाएगा।

(सदन द्वारा 2 मिनट का मौन धारण किया गया।)

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: ओम शांति शांति शांति। अब सचिव विधान सभा उप राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगे। सब अपने एक,

सचिव (दिल्ली विधान सभा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण की हिंदी तथा अंग्रेजी प्रति सदन पटल पर प्रस्तुत करता हूँ।[1] यह आपके टैबलेट्स में अवेलेबल है

माननीय उप-राज्यपाल का अभिभाषण

माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगण,

1. मैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आठवीं विधानसभा के, चौथे सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूँ ।

[1] दिल्ली विधान सभा पुस्तकालय में संदर्भ संख्या आर-23447 पर उपलब्ध।

2. आज, मैं अपनी सरकार की कुछ उपलब्धियों, और कुछ नई नीतियों का, संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो दिल्ली के नागरिकों को, उनके लक्ष्यों, और आकांक्षाओं की पूर्ति करने की दिशा में, कार्यान्वित की जा रही हैं।

3. विशाल जनादेश द्वारा, दिल्ली की जनता ने, मेरी सरकार और उसके संकल्प पत्र में समाहित नीतियों पर, विश्वास व्यक्त किया है। मेरी सरकार, इस जनादेश में समाहित, अपनी जिम्मेदारियों से अवगत है, और इन जिम्मेदारियों के समुचित निर्वहन के लिए, कृतसंकल्प है।

4. मेरी सरकार के सम्मुख, सबसे बड़ी चुनौती, शासन तथा प्रशासन में, वर्षों से व्याप्त जड़ता, तथा नकारात्मकता से, निपटने की थी। लगभग दस महीने के अल्प-काल में, मेरी सरकार ने, इस दिशा में अनेक महत्वपूर्ण, तथा ठोस कदम उठाये हैं।

5. महात्मा गाँधी के सर्वोदय, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अन्त्योदय, तथा बाबा साहेब के समता के सिद्धांतों के अनुरूप, पिछले दस महीनों में, मेरी सरकार ने, दिल्ली के सभी नागरिकों के कल्याण के दिशा में, अनेक अप्रत्याशित निर्णय लिए, जिनका क्रियान्वयन जारी है।

माननीय सदस्यगण,

6. इस वर्ष सरकार ने, ₹1 लाख करोड़ रुपये का एक ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया, जो सभी दस प्रमुख प्राथमिक क्षेत्रों पर केंद्रित है। यह प्राथमिक क्षेत्र, Infrastructure, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, Environmental Sustainability तथा सामाजिक न्याय हैं।

7. सरकार ने 'Ease of Doing Business' के तहत, व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सरल बनाया है, अनावश्यक नियामक बाधाओं को कम किया है, तथा निवेश आकर्षित करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत सुधार किये हैं। इनमें लाइसेंसिंग तथा श्रम संबंधी सुधार, आदि प्रमुख हैं।

8. उत्तम सेवा एवं पारदर्शिता लाने के लिए, इ-गवर्नेंस द्वारा विभिन्न विभागों से जुड़ी 75 ई-डिस्ट्रिक्ट सर्विसेज को, सिटीज़न सर्विस सेंटर्स (CSCs) के साथ, सफलतापूर्वक जोड़ दिया गया है। सरकार के कार्य ग्रहण के पांच महीने के भीतर, प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए, सभी सरकारी कार्यालयों में e-Office का क्रियान्वयन किया गया है, जो कि काफी समय से लंबित था।

9. इसी प्रकार, Ease of Doing Business की पहल के तहत, शराब की दुकानों को छोड़कर, सभी दुकानों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को, 24x7 खोलने की अनुमति प्रदान की गयी है। साथ ही 21 वर्षों में पंजीकरण के अनिवार्य नवीनीकरण की व्यवस्था को भी, समाप्त कर दिया गया है। इस कदम से, व्यापारियों को, अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाओं से, राहत मिलेगी। इसी के साथ, दिल्ली दुकानें एवं प्रतिष्ठान अधिनियम में, अन्य संशोधनों के लिए भी, एक विधेयक लाया जा रहा है। अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र, भू-उपयोग परिवर्तन, फैक्ट्री और व्यापार लाइसेंस आदि को, प्राप्त करना आसान कर दिया गया है। 29 मौजूदा श्रम कानूनों को, समाहित कर, उन्हें चार व्यापक लेबर कोड्स में, एकीकृत करते हुए, सरकार ने केंद्र सरकार के साथ पूर्ण समन्वय में, आगे बढ़ने का महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इन श्रम संहिताओं के माध्यम से, न केवल कानूनों की जटिलता को कम किया गया है, बल्कि श्रमिकों को, सामाजिक सुरक्षा, बेहतर कार्य परिस्थितियाँ, और समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में भी, ठोस प्रयास किए गए हैं। बहुत ही कम समय में, इन सभी सुधारों को लागू करने के लिए, मैं मुख्यमंत्री महोदया के नेतृत्व वाली सरकार का, साधुवाद करता हूँ।

10. यह सुनिश्चित करने के लिए कि, विकास का लाभ दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र तक पहुँचे, सरकार ने 'जिला परियोजना निधि योजना' की शुरुआत की है। 1400 करोड़ रूपए की राशि के साथ, मुख्यमंत्री विकास निधि को, पूंजीगत एवं आधारभूत संरचना संबंधी, आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, स्वीकृति प्रदान की गई है।

माननीय सदस्यगण,

11. मेरी सरकार ने, स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए, अपने कुल व्यय का 13 प्रतिशत आवंटित किया है, जो अन्य राज्यों द्वारा, स्वास्थ्य पर किए जाने वाले औसत व्यय की तुलना में, उल्लेखनीय रूप से अधिक है।

12. Health Infrastructure को मजबूत करने के लिए 17 अस्पतालों में, विभिन्न निर्माण कार्य किये जा रहे हैं। इसी क्रम में, सितंबर 2025 में, 5 अस्पताल ब्लॉकों का, उद्घाटन किया गया।

13. फरवरी 2025 में, नई सरकार के गठन के पश्चात, स्वास्थ्य क्षेत्र में लिया गया पहला बड़ा निर्णय, **'आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना'** को, लागू करना रहा। अब तक 6 लाख,72 हजार, 551 आयुष्मान कार्ड जारी किए जा चुके हैं। इनमें, 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए, 2 लाख, 62 हजार, 383 वय वंदना योजना कार्ड, शामिल हैं। योजना के अंतर्गत, दिल्ली में

188 अस्पताल - 137 निजी एवं 51 सरकारी - इम्पैनल किए गए हैं। इसके तहत, अब तक 19,287 मरीजों का, सफल उपचार किया गया है।

14. PM-ABHIM योजना के अंतर्गत, **238 आयुष्मान आरोग्य मंदिर**, संचालित किए जा रहे हैं। इससे प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं, सुदृढ़ हुई हैं, और बड़े अस्पतालों पर भार कम हुआ है। किफायती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु, **29 जन औषधि केंद्र**, भी कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, 11 एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएँ, तथा 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉक, स्थापित किए जाने की योजना पर, कार्य जारी है।

15. डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत, 37 अस्पतालों में **हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम**, लागू किया गया है।

16. एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में, दिल्ली सरकार ने, राष्ट्रीय आयुष मिशन को लागू करने, तथा **'दिल्ली राज्य आयुष सोसाइटी'** के गठन को, स्वीकृति प्रदान की है। इससे, आयुष चिकित्सा पद्धतियों का समग्र विकास, सुनिश्चित किया जा सकेगा। आपातकालीन सेवाओं को, और सुदृढ़ करते हुए, 53 नई एंबुलेंस जोड़ी गई हैं, जिससे एंबुलेंस की कुल संख्या 330 हो गई है।

17. प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, तथा पी.पी.पी. डायलिसिस परियोजना के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को, निःशुल्क, तथा सामान्य नागरिकों को, किफायती हीमो-डायलिसिस सेवाएँ, उपलब्ध कराई जा रही हैं। वर्तमान में, 16 डायलिसिस केंद्रों में, 300 मशीनें कार्यरत हैं, जिनमें मेरी सरकार ने, बहुत ही कम समय में ही, 150 मशीनें लगवाई है। पिछले कुछ महीनों में, **926 नर्सिंग अधिकारी, 141 पैरा-मेडिकल कर्मी तथा 127 नॉन-टीचिंग विशेषज्ञों** की नियुक्ति की गई है, जिससे स्वास्थ्य संस्थानों में, रोगी-सेवा, और अधिक सशक्त हुई है। मेरी सरकार ने **नर्सिंग इंटर्न के स्टाइपेंड को, 500 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर, 13,150 रुपये प्रति माह कर दिया।** सरकार का यह कदम, प्रशंसनीय है।

18. इसके साथ ही, मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए, द्वारका में, दिल्ली का पहला **Brain Health Clinic** भी, प्रारंभ किया गया है।

माननीय सदस्यगण,

19. मेरी सरकार का दृढ़ विश्वास है, कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्रत्येक बच्चे का मौलिक अधिकार है, न कि विशेषाधिकार। इसी सोच के साथ, वर्ष 2025-26 में, शिक्षा क्षेत्र के लिए, **कुल बजट का, 19 प्रतिशत**, आवंटित किया गया है। यह आवंटन, दर्शाता है कि, सरकार शिक्षा को, भविष्य में, सकारात्मक निवेश के रूप में, देखती है।

20. निजी विद्यालयों द्वारा, मनमानी शुल्क वृद्धि की समस्या से निपटने के लिए, **"दिल्ली स्कूल शिक्षा (शुल्क निर्धारण एवं विनियमन में पारदर्शिता) अधिनियम, 2025"**, पारित किया गया है। यह कानून शिक्षा को व्यवसाय बनने से, रोकने की दिशा में, एक ऐतिहासिक कदम है।

21. 'जनता के राष्ट्रपति', डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम की स्मृति, और विरासत को सम्मान देने के उद्देश्य से, दिल्ली के सरकारी विद्यालयों में, **100 डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम, भाषा प्रयोगशालाओं** की, स्थापना की जा रही है। इन प्रयोगशालाओं में, अत्याधुनिक तकनीक, और AI का उपयोग कर, अंग्रेज़ी, हिंदी, अन्य भारतीय भाषाएँ, एवं फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी, विदेशी भाषाओं का शिक्षण भी, कराया जाएगा।

22. **राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020** के अंतर्गत, पी.एम. श्री विद्यालयों की अवधारणा से प्रेरित होकर, दिल्ली में **75 सी.एम. श्री विद्यालयों** की, शुरुआत की गयी है। इन विद्यालयों में, प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, आधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय आदि सुविधाएं होंगी।

23. कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए, सभी सरकारी विद्यालयों में, **स्मार्ट कक्षाओं की स्थापना** की जा रही है। आज के डिजिटल युग में, तकनीक तक पहुँच, कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत, कक्षा 10वीं से 11वीं में, प्रवेश लेने वाले 1,200 मेधावी विद्यार्थियों को, निःशुल्क लैपटॉप प्रदान किये जाने की, योजना पर कार्य जारी है।

24. CBSE द्वारा निर्धारित आधुनिक शिक्षा मानकों को पूरा करने के लिए, सरकारी विद्यालयों में, 175 IT Labs की स्थापना की जा रही है, जिनमें प्रत्येक प्रयोगशाला में, 40 कंप्यूटर उपलब्ध होंगे।

25. मेरी सरकार ने, खिलाड़ियों के लिए, खेल प्रोत्साहन राशि को दोगुना से ज्यादा बढ़ाकर, सराहनीय कार्य किया है। इसके अंतर्गत, ओलंपिक तथा पैरा-ओलंपिक खेलों में, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक विजेताओं को, क्रमशः ₹7 करोड़, ₹5 करोड़ और ₹3 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि, देने का निर्णय लिया है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है। इसके अतिरिक्त, एशियाई, कामनवेल्थ व् अन्य अंतरराष्ट्रीय व

राष्ट्रीय खेलों में भी, खेल प्रोत्साहन राशि को, डेढ़ से तीन गुना तक, बढ़ाया गया है। खेलों और खिलाड़ियों के लिए, सरकार के समर्पण को, मैं साधुवाद देता हूँ।

26. मेरी सरकार ने, वर्ष 2025-26 के बजट में, Capital Expenditure को दोगुना करते हुए, लगभग 28,000 करोड़ रुपये किया है। इसका उद्देश्य, केवल ढांचागत निर्माण करना नहीं, बल्कि दिल्ली को, भविष्य के लिए, एक ऐसी राजधानी के रूप में, तैयार करना है, जो गति, सुविधा और स्थिरता का संतुलन, प्रस्तुत करे।

27. इलेक्ट्रिक वाहन पहल के अंतर्गत, भारत सरकार के सहयोग से, लगभग 3535 इलेक्ट्रिक बसें शामिल हैं, जिनमें से लगभग 1150 DEVI बसें, Last Mile Connectivity को मजबूत करने के लिए, चलाई जा रही हैं। इसके साथ ही, 36,000 इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट्स, की स्थापना की योजना पर भी, कार्य किया जा रहा है।

28. सरकार बसों और मेट्रो के बीच, सहज यात्रा सुनिश्चित करने के लिए, NCMC (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड), लागू करने की योजना पर, कार्य कर रही है, जो दोनों परिवहन साधनों में, मान्य होगा। दिल्ली की महिलाओं को, यह सुविधा निःशुल्क, पिंक कार्ड के रूप में, प्रदान की जाएगी।

29. सरकार ने, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए, मेट्रो फेज-4 के लिए, लगभग 3300 करोड़ रूपए का प्रावधान किया है। साथ ही, माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, दिल्ली-मेरठ नमो भारत रेल सेवा, शुरू कर दी गयी है, जिसके लिए सरकार, माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति कृतज्ञ है।

30. मेरी सरकार ने, थोड़े ही समय के कार्यकाल में, 150 किमी सड़कों, का नवीनीकरण किया है, एवं 400 किलोमीटर सड़कों का निर्माण, और पुनर्विकास, मार्च 2026 तक, पूरा कर लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, 600 किलोमीटर सड़कों का नवीनीकरण, वर्ष 2026 में नियोजित है। मेरी सरकार संकल्पकृत है, कि बची हुई 300 किमी सड़कें भी, वित्त वर्ष 2026-27 के अंत तक, पूरी तरह से, नवीनीकृत कर ली जाए।

31. कई वर्षों के बाद, सरकार को सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से, 803 करोड़ रूपए की, केंद्रीय सहायता प्राप्त हुई है। इसके साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से, दिल्ली की

तीन प्रमुख सड़कों — एम.जी. रोड, मथुरा रोड और रोहतक रोड — के विकास की योजना पर, कार्य चल रहा है।

32. मेरी सरकार, द्वारका एक्सप्रेसवे के दिल्ली सेक्शन, तथा अर्बन एक्सटेंशन रोड-II के निर्माण के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, हार्दिक आभार व्यक्त करती है। 11,000 करोड़ रुपये की लागत से बनी, ये परिवर्तनकारी परियोजनाएँ, दिल्ली में, यातायात जाम को कम करेंगी, यात्रा समय घटाएँगी, और दिल्ली-एन.सी.आर. क्षेत्र में, संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगी।

33. काफी समय से लंबित, नंद नगरी फ्लाईओवर का कार्य भी, मेरी सरकार ने, काफी कम समय में पूर्ण किया है, जिससे ट्रांस यमुना क्षेत्र की, अनेक कॉलोनियों का, दिल्ली और एन.सी.आर. से, बेहतर संपर्क संभव हो सका है। बारापुला फ्लाईओवर को, पूर्ण करने का कार्य, जो वर्षों से लंबित था, दोबारा शुरू किया गया है, एवं अब सभी आवश्यक अनुमतियाँ प्राप्त करने के बाद, मई 2026 तक पूरा करने की योजना है। इसी प्रकार, मोदी मिल, और सावित्री सिनेमा पर, नए फ्लाईओवरों का निर्माण भी, स्वीकृत किया गया है।

34. जलभराव, दिल्ली की एक दीर्घकालिक समस्या रही है, विशेषकर मानसून के दौरान। इस दिशा में, सरकार ने, सक्रिय और प्रभावी कदम उठाए हैं। युद्धस्तर पर, नालों की गाद निकासी की गई है, और अब तक, लगभग 22 लाख मीट्रिक टन गाद, हटाई गई है। सीवर लाइनों की नियमित सफाई की जा रही है, तथा संवेदनशील क्षेत्रों में, जलभराव की समस्या को, रोकने के लिए, रियल-टाइम मॉनिटरिंग युक्त, Smart Drainage Systems, विकसित की जा रही हैं।

35. लगभग पचास वर्षों के बाद, पूरे दिल्ली के लिए, एक नया ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसे आने वाले वर्षों में, 56,000 करोड़ रूपए की लागत से, लागू किया जाएगा।

36. केंद्र द्वारा पारित, तीनों आपराधिक कानूनों को, दिल्ली में भी, सुचारु रूप से लागू किया गया। न्यायालयों की Infrastructure सुधारने, तथा फैमिली कोर्ट, आवासीय भवन, अधिवक्ता कक्ष, और नए न्यायालय परिसरों जैसी, सुविधाएँ उपलब्ध कराने के लिए, परियोजनाएँ प्रारंभ की गई हैं। नरेला में, उच्च सुरक्षा जेल परिसर के निर्माण को भी, स्वीकृति प्रदान की जा रही है। E-forensic System लागू कर दिया गया है, जो सरकार की न्याय के प्रति, प्राथमिकता को दर्शाता है।

37. झुग्गी वासियों के सतत और समग्र विकास के लिए, मेरी सरकार कृतसंकल्प है। पिछली सरकार के समय के बने, जर्जर हो चुके, EWS फ्लैट्स के, नवीनीकरण का कार्य कराकर, सरकार द्वारा, गरीब परिवारों को घर दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही, इन कॉलोनियों में, बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए, लगभग 700 करोड़ रुपये का प्रावधान, रखा गया है। इन कॉलोनियों में, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अटल कैंटीन की सुविधा भी, दी जा रही है। सामाजिक कल्याण के प्रति, अपनी दृढ़ प्रतिबद्धता के तहत, मेरी सरकार ने 'अटल कैंटीन योजना' प्रारंभ की है, जिसके अंतर्गत, मात्र 5 रुपये में, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर, संकल्पित 100 में से, 45 अटल कैंटीनों का शुभारंभ, किया गया है, तथा शेष कैंटीनें भी, शीघ्र ही प्रारंभ की जाएँगी। गरीब परिवारों के सुविधाओं और सम्मान के लिए, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार के, इस कदम का मैं स्वागत करता हूँ।

माननीय सदस्यगण,

38. वर्षों की उपेक्षा, और प्रदूषण के कारण, यमुना नदी की स्थिति दयनीय रही है। मेरी सरकार ने आते ही, यमुना की स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। यमुना rejuvenation हेतु, कई स्तर पर, एक साथ कार्य किए जा रहे हैं। नए STP लगाए जा रहे है, और वर्तमान STPs के, upgradation के कार्य, प्राथमिकता के साथ, किये जा रहे हैं। इन सभी पहलों का प्रभाव, आने वाले समय में, दिखाई देगा। ऐसे सारे नालें, जो यमुना को प्रदूषित करते हैं, उन्हे टैप करके ट्रीट करने के लिए, decentralized STPs लगाने की, योजना पर भी, सरकार कार्यरत है।

39. दिल्ली जल बोर्ड को, जलापूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, 9,000 करोड़ रूपए का, आवंटन किया गया है। जलापूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से, Water Treatment Plants की क्षमता, बढ़ाई जा रही है। सरकार अपशिष्ट जल के recycling को भी प्रोत्साहित कर रही है, और नजफगढ़ नाले तथा यमुना के बाढ़ क्षेत्र जैसे, जल स्रोतों के, पुनर्जीवन के लिए, निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। ड्रेनों की सिल्ट सफाई, और इनमें गिरने वाले गोबर की, रोकथाम के लिए, बायोगैस प्लांट लगाने के कार्य भी, प्रारंभ किए गए हैं।

40. नवंबर 2025 में, सरकार ने एक महत्वपूर्ण और जनहितकारी निर्णय लेते हुए, उन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया, जिनके कारण, दिल्ली नगर निगम द्वारा, अनधिकृत निर्माण के लिए 'बुक' की गई संपत्तियों को, बिजली कनेक्शन नहीं दिया जा रहा था। इस निर्णय के बाद, अब बिजली वितरण

कंपनियाँ, केवल इस आधार पर बिजली कनेक्शन देने से इनकार नहीं कर सकतीं, या आपूर्ति बाधित नहीं कर सकतीं, कि कोई संपत्ति, नगर निगम की, 'बुक' की गई सूची में, शामिल है। इस नीति परिवर्तन से, दिल्ली के एक लाख पच्चीस हजार से अधिक, परिवारों को लाभ हुआ है। ऐसे घर, पहले इन प्रतिबंधों के कारण, बिजली सुविधा से वंचित थे, और अब, वैध रूप से, बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकते हैं।

माननीय सदस्यगण,

41. दिल्ली में वर्षों से लंबित, पी. एम. स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए, दिल्ली आबादी देह सर्वेक्षण, एवं अभिलेख संचालन नियम, 2025, अधिसूचित किया गया है। इससे, ग्रामीण क्षेत्रों में लाल डोरा आबादी को, पहली बार संपत्ति के वैधानिक अधिकार, प्राप्त होंगे। मैं इस ऐतिहासिक कार्य के लिए, मेरी सरकार को बधाई देता हूँ।

42. प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाने, और नागरिक सेवाओं तक, जनता की आसान पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, दिल्ली सरकार ने, **सुशासन दिवस, 25 दिसंबर 2025 से**, अपने 11 राजस्व जिलों का पुनर्गठन कर, 13 नए जिले बनाए हैं, ताकि MCD ज़ोन, NDMC, और दिल्ली कैंट के साथ, सीमाएँ, समन्वित हो सकें। जनहित के लिए किये गए, इस प्रशासनिक सुधार के लिए, सरकार प्रशंसा की पात्र है।

43. इसके साथ ही, सभी 13 जिलों में, **मिनी सचिवालयों** की स्थापना को, मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है। ये बहु-विभागीय केंद्र, एक ही भवन में, सभी सेवाएं उपलब्ध कराएंगे, और नागरिकों के लिए, एकल संपर्क बिंदु के रूप में, कार्य करेंगे।

44. एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत, **साप्ताहिक जन-सुनवाई** के माध्यम से, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी और उप-जिलाधिकारी, सीधे नागरिकों की समस्याएं सुनकर, उनके त्वरित समाधान के लिए, आवश्यक निर्देश दे रहे हैं।

45. जनता की शिकायतों के समयबद्ध निवारण, प्रभावी सेवा वितरण, सूचनाओं के व्यापक प्रसार तथा नागरिकों के सुझावों और विचारों को, प्राप्त करने के उद्देश्य से, **'दिल्ली मित्र ऐप'** की परिकल्पना

की गई है। **जन शिकायत निवारण प्रबंधन के लिए, web-portal development** का कार्य, भी जारी है।

46. इसके साथ ही, **'विकसित दिल्ली इंटर्नशिप कार्यक्रम'** के अंतर्गत, 85 युवाओं को जोड़ा गया है। पर्यटन क्षेत्र को सुदृढ़ करने, और विरासत संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, सरकार ने **पर्यटन एवं विरासत फेलोशिप कार्यक्रम** को भी, स्वीकृति प्रदान की है।

47. **आंगनवाड़ी केंद्रों को**, सरकारी भवनों में सह-स्थापित (को-लोकेशन), तथा सरकारी विद्यालयों के साथ, मैप भी किया गया है। 502 आंगनवाड़ी-सह-शिशुगृह - **'पालना'**, भी शुरू किए गए हैं। महिलाओं की कार्यबल में, भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, सरकार ने प्रतिबंधों को हटाते हुए, उन्हें दिल्ली में, नाइट शिफ्ट में कार्य करने की अनुमति देने का, निर्णय भी लिया है।

48. समाज के, वंचित वर्गों के कल्याण हेतु, पश्चिम विहार में, सावित्रीबाई फुले वरिष्ठ नागरिक गृह, तिमारपुर में अटल दृष्टि गृह, तथा नरेला में, अटल आशा गृह की स्थापना कर, इन्हें आम जन के लिए, खोल दिया गया है।

49. इसके अतिरिक्त, GRAP के दौरान, दिल्ली एन.सी.आर. में, निर्माण गतिविधियों पर लगाए गए, प्रतिबंध के मद्देनजर, निर्माण श्रमिकों के हितों की रक्षा करते हुए, भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को, आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस क्रम में, प्रत्येक योग्य श्रमिक को, **10,000 रुपये की अनुग्रह राशि** वितरित की गई, जिससे कठिन समय में, उनकी आजीविका को सहारा मिल सके।

50. **दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड** को, सरकार ने, पुनर्जीवित किया, जिसके तहत, लगभग **1,715 करोड़ रुपये** की अनुमानित लागत वाली, **776 विकास परियोजनाओं** पर, कार्य किया जाएगा।

51. व्यापक देखभाल की आवश्यकता वाले, दिव्यांगजनों को, अन्य पेंशनों के अतिरिक्त, **प्रतिमाह 6,000 रुपये की सहायता** की, भी मंजूरी दी गयी है, जिससे, देखभाल कर्ताओं की व्यवस्था, उपचार तथा सहायक उपकरणों की लागत को, पूरा करने में, मदद मिलेगी।

52. **1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के आश्रितों को**, अनुकंपा के आधार पर, सरकारी नौकरी हेतु, सरकार ने एक नई नीति को मंज़ूरी दी है, और अब तक, 56 लाभार्थियों को नौकरियां प्रदान की गयी हैं। इसके अतिरिक्त, दिल्ली में रह रहे, जम्मू-कश्मीर प्रवासियों को, एकमुश्त राहत प्रदान करते हुए, आय की शर्त समाप्त कर दी गई है।

53. देश की राजधानी होने के नाते, तथा एकता और सांस्कृतिक विविधता का उदाहरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, सरकार ने, भारत के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के, **'स्थापना दिवस'** मनाना, प्रारम्भ किया है। इसके अतिरिक्त, पर्यटन विभाग द्वारा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, आम महोत्सव, और तीज महोत्सव जैसे, महत्वपूर्ण दिवसों और उत्सवों का आयोजन किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में, आम जनता की सहभागिता, अत्यंत उत्साहजनक, और सराहनीय रही है।

54. पहली बार **कांवड़ समितियों को Single Window System** के माध्यम से, सीधे **DBT** के द्वारा, वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। परिणामस्वरूप, इस वर्ष आयोजित कांवड़ यात्रा, अत्यंत सफल रही। सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं के संरक्षण एवं प्रोत्साहन के उद्देश्य से, तथा आयोजन समितियों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ को कम करने के लिए, सरकार ने, **रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों को**, 1200 यूनिट तक, निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई है। यमुना के घाटों पर, इस वर्ष, बेहतरीन तरीके से, **छठ महापर्व एवं दीपोत्सव का आयोजन हुआ**, जिसमें लाखों लोगों ने भाग लिया। इसी तरह, गुरु तेग बहादुर जी का, 350वां बलिदान दिवस और वीर बाल दिवस भी मनाया गया।

55. मेरी सरकार का, यह दृढ़ विश्वास है कि, सभी सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं का सम्मान करते हुए, नागरिकों को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करना ही, समावेशी और संवेदनशील शासन की पहचान है।

माननीय सदस्यगण,

56. वायु प्रदूषण, आज हमारे शहर के सामने, सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है। स्वच्छ वायु कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का, मौलिक अधिकार है।

57. **प्रदूषण नियंत्रण** पर मेरी सरकार, पूर्णतः प्रतिबद्ध है। पूर्व वर्षों की तरह, केवल मौसमी उपायों तक सीमित रहने के बजाय, सरकार ने, जून 2025 में ही, एक व्यापक, वर्षभर लागू होने वाली, और समयबद्ध, **वायु प्रदूषण न्यूनीकरण योजना आरंभ की**। यह योजना, रोकथाम, आधुनिक तकनीक के उपयोग, कड़े प्रवर्तन तथा जनभागीदारी पर केंद्रित है, जिसमें, सभी विभागों, स्थानीय निकायों और एनसीआर की एजेंसियों के, समन्वित प्रयास शामिल हैं।

58. वायु गुणवत्ता की निगरानी को, सुदृढ़ करने हेतु, **6 नए Air Quality Monitoring Station**, स्थापित किए जा रहे हैं। इससे Real-time data की उपलब्धता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।

प्रभावी उपायों को अपना कर, विकास विभाग ने, **2025 की सर्दियों में, दिल्ली में पराली जलाने की घटनाओं को, शून्य कर दिया।**

59. इसके अलावा, हर वर्ष, लगभग **2.5 लाख वाणिज्यिक वाहनों की**, तकनीक-आधारित **फिटनेस जांच** के लिए, नंद नगरी, बुराड़ी और तेहखंड में, **तीन ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन, (ATS) स्थापित करने का कार्य**, त्वरित गति से किया जा रहा है।

60. हाल के सप्ताहों में, प्रदूषण स्तर बढ़ने पर, सरकार ने तुरंत जमीनी स्तर पर कदम उठाए। 1800 से अधिक, दिन-रात कार्यरत निरीक्षण टीमें, तैनात की गई हैं। **'एक पेड़ माँ के नाम'** अभियान के अंतर्गत, हरित आवरण का, विस्तार किया जा रहा है। केवल दस महीनों में, 1450 इलेक्ट्रिक बसों को शामिल कर, non-polluting public transport को, सशक्त किया गया है। कई routes पर, Inter-State EV बसों की भी, शुरुआत की गयी है। धूल नियंत्रण के लिए, डबल शिफ्ट में, Mechanical Road Sweepers, जल छिड़काव, और एंटी-स्मॉग गन का, व्यापक उपयोग किया जा रहा है। Sanitation व्यवस्था सुदृढ़ करने, एवं प्रदूषण नियंत्रण के मकसद से, MCD को 10 वर्षों के लिए, **70 MRSM, और, 1000 Litter Picker Machines** के लिए, **2300 करोड़ रूपए की**, वित्तीय सहायता प्रदान करने का, निर्णय लिया गया है।

61. शीत ऋतु में, खुले में आग जलाने की घटनाओं को रोकने हेतु, RWAs को **3,000 इलेक्ट्रिक हीटर, निःशुल्क वितरित** किए गए हैं, और शहर में, 24x7, निर्बाध बिजली आपूर्ति, सुनिश्चित की गई है।

62. मेरी सरकार ने, दिल्ली नगर निगम (MCD) को इस वर्ष, 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान दिया है, तथा आगे प्रति वर्ष, 300 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा, जो कि, कूड़ा निस्तारण, और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में, तेजी लाएगा।

63. दिल्ली सरकार, PPP मॉडल के तहत, होलंबी कलां में, दिल्ली का पहला, **एकीकृत ई-वेस्ट ईको पार्क** स्थापित करने की दिशा में, कार्य कर रही है। इस पहल के फलस्वरूप, प्रतिवर्ष, 51,000 टन से अधिक, ई-कचरे का वैज्ञानिक तरीके से, treatment किया जाएगा।

64. सरकार, बायोमाइनिंग और Waste-to-Energy तकनीकों से, गाज़ीपुर, भलस्वा और ओखला लैंडफिल को साफ़ कर रही है। 2027 तक की समयसीमा के तहत, ट्रोमेल मशीनों और PPP मॉडल के तहत, कचरे के पहाड़ों पर जमा कूड़ा हटाकर, दिल्ली को कचरा-मुक्त बनाने का, लक्ष्य है।

65. वाहन प्रदूषण नियंत्रण भी, सरकार का एक प्रमुख focus area है। इलेक्ट्रिक बसों, Last-mile e-mobility, और तेजी से विस्तार किये जा रहे, EV Charging Network के माध्यम से, दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली, निरंतर मजबूत हो रही है। दिसंबर 2026 तक, संशोधित ई.वी. नीति के तहत, बसों के बेड़े में, 7700 से अधिक स्वच्छ ईंधन बसें जोड़ी जाएंगी। यातायात जाम, और उससे होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सरकार ने 600 अतिरिक्त कर्मी, लगाए हैं।

66. C&D मलबा, जो वर्तमान में लगभग 6,000 टन प्रतिदिन है, के व्यवस्थित निस्तारण के लिए, चार प्रोसेसिंग प्लांट पहले से कार्यरत हैं तथा 1,000 TPD क्षमता का, एक नया प्लांट, दिसंबर 2026 तक, चालू किया जाएगा। इसके साथ ही, सरकारी परियोजनाओं में प्रोसेस्ड कचरे के अनिवार्य पुनः उपयोग के माध्यम से, circular economy को, बढ़ावा दिया जा रहा है।

67. सड़क धूल नियंत्रण को, विशेष प्राथमिकता दी गई है। सभी श्रेणियों की सड़कों को शामिल करते हुए, एक व्यापक सड़क पुनर्विकास एवं greening योजना, तैयार की गई है, जिसे बड़े पैमाने पर, यांत्रिक सफाई और जल छिड़काव प्रणालियों के साथ, अगले शीतकाल से पहले, पूरी तरह लागू किया जाएगा।

68. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण कार्य को, नियमित निरीक्षण, वास्तविक समय निगरानी और अवैध इकाइयों पर सख्त कार्रवाई के माध्यम से, मजबूत किया गया है। केवल स्वच्छ उद्योगों को अनुमति देने के लिए, नई औद्योगिक नीति तैयार की जा रही है।

69. इन प्रयासों को और मजबूती देने के लिए, कई पहल किये गए हैं। इनमें, ऊँची व्यावसायिक इमारतों पर, एंटी-स्मॉग प्रणालियों की अनिवार्यता, प्रदूषण हॉटस्पॉट पर मिस्ट स्प्रे सिस्टम की स्थापना, तथा "No PUCC No Fuel" नीति का, सख्त प्रवर्तन शामिल है। इसके अतिरिक्त, सड़कों पर PWD, DDA, NDMC एवं DMRC द्वारा, अब तक 650 से अधिक, मिस्ट स्प्रे सिस्टम लगा दिए गए हैं।

70. स्वच्छ वायु एक साझा जिम्मेदारी है। सरकार के प्रयास, तभी सफल हो सकते हैं, जब नागरिकों का, सक्रिय सहयोग प्राप्त हो। विद्यालयों, RWAs और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से, जन-जागरूकता, और सहभागिता को निरंतर बढ़ाया जा रहा है। साथ ही, दिल्ली को हरित शहर बनाने की प्रतिबद्धता, के तहत अधिक पेड़ लगाने का लक्ष्य है। इस दिशा में, आगामी चार वर्षों में, लगभग 35 लाख वृक्ष तथा 63 लाख झाड़ियां, लगाई जाएंगी। इसके साथ ही, स्वदेशी पेड़, जैसे नीम, आम, बरगद, पीपल आदि के, वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। Solarization को बढ़ावा देने के लिए,

सरकार ने, PM सूर्य घर योजना के तहत, स्टेट सब्सिडी को, 2000 रुपए प्रति किलोवाट को बढ़ाकर, 10,000 रुपए प्रति किलोवाट, कर दिया है।

माननीय सदस्यगण,

71. यद्यपि सरकार ने अनेक उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं, फिर भी, कई चुनौतियों पर पार पाना, बाकी है। सरकार सभी चुनौतियों का सामना पूर्ण दृढ़ता, प्रतिबद्धता और पारदर्शिता के साथ कर रही है, तथा इस विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है कि, सामूहिक प्रयासों से, इन बाधाओं को, अवसरों में परिवर्तित, किया जा सकता है।

72. मैंने, आपके समक्ष अपनी सरकार की प्रमुख विकासोन्मुख नीतियों, और जनकल्याणकारी योजनाओं की, एक संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की है। मुझे आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि, सभी माननीय सदस्य, जनहित को सर्वोपरि रखते हुए, सरकार को अपना सहयोग प्रदान करेंगे, जन-आकांक्षाओं की पूर्ति में सहभागी बनेंगे, तथा इस प्रतिष्ठित सदन की गरिमा को, अक्षुण्ण बनाए रखेंगे।

माननीय सदस्यगण,

73. जनप्रतिनिधियों का यह संवैधानिक दायित्व है कि, वे जिन नागरिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को, सकारात्मक नेतृत्व और सार्थक दिशा प्रदान करें। सार्वजनिक नीतियों के निर्माण, तथा शासन की प्रक्रियाओं को दिशा देने में, आपकी भूमिका, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा करके आप जनता की आशाओं को ठोस परिणामों, और समावेशी विकास में, रूपांतरित कर सकेंगे।

74. मेरी यह आशा और अपेक्षा है कि, इस सम्मानित सदन की कार्यवाहियाँ, परिपक्वता, विवेक, सहयोग, तथा स्वस्थ लोकतांत्रिक विमर्श की भावना के साथ, संपन्न होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि, निःस्वार्थ सेवा की भावना और जनता के कल्याण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता, से प्रेरित होकर, इस सदन की कार्यवाही, दिल्ली के समग्र विकास, और प्रगति में, सार्थक योगदान देगी।

75. इन शब्दों के साथ, मैं आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ, और आप सभी के उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करता हूँ।

जय हिंद !

Address of Hon'ble Lt. Governor

Hon'ble Speaker and Members,

1. I extend a warm welcome to all of you to the Fourth Session of the Eighth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi.

2. Today, I am presenting a brief account of some of the achievements of my Government, as well as certain new policies that are being implemented to enable the citizens of Delhi to realise their goals and aspirations.

3. Through an overwhelming mandate, the people of Delhi have expressed their faith in my Government and in the policies embodied in its manifesto. My Government is fully conscious of the responsibilities inherent in this mandate and is firmly committed to discharging them with due diligence and dedication.

4. The foremost challenge before my Government has been to overcome the inertia and negativity that had pervaded governance and administration for years. Within a short span of nearly ten months, my Government has taken several significant and concrete steps in this direction.

5. In keeping with the principles of Sarvodaya espoused by Mahatma Gandhi, Antyodaya envisioned by Pandit Deendayal Upadhyaya and equality championed by Babasaheb, my Government has, over the past ten months, taken several bold and unprecedented decisions aimed at the welfare of all citizens of Delhi, the implementation of which is currently underway.

Hon'ble Members,

6. This year, the Government has presented **a historic budget of ₹1 lakh Crore**, focused on all ten major priority sectors. These primary sectors are Infrastructure, Education, Health, Women's Welfare, Water Supply, Electricity, Roads, Industrial Development, Environmental Sustainability and Social Justice.

7. Under the *Ease of Doing Business* framework, the Government has simplified business processes, reduced unnecessary regulatory hurdles and undertaken policy reforms across various sectors to attract investment. In which, reforms related to licensing and labour regulations etc. are important.

8. To ensure improved service delivery and greater transparency, **75 e-District services** across various departments have been successfully integrated with **Citizen Service Centres (CSCs) through e-governance.** Within five months of assuming office, the

Government implemented the long-pending **e-Office system across all Government offices** to enhance transparency in administration.

9. Similarly, as part of the Ease of Doing Business initiative, all Shops and commercial Establishments—except liquor shops—have been permitted to operate **24×7**. As well as, mandatory renewal of registration after 21 years has also been abolished. This step will provide relief to traders from unnecessary administrative procedures. Simultaneously, a Bill is being introduced to bring further amendments to the Delhi Shops and Establishments Act. Procedures for obtaining fire safety certificates, change of land use, factory licences and trade licences have been simplified. By subsuming 29 existing Labour Laws into **four comprehensive Labour Codes**, the Government has taken an important step forward in full coordination with the Central Government. These Labour Codes not only reduce the complexity of laws but also make concrete efforts towards providing social security, better working conditions and timely justice to workers. I commend the Government led by the Hon'ble Chief Minister for implementing these wide-ranging reforms within a very short period.

10. To ensure that the benefits of development reach every region of Delhi, the Government has launched the *District Project Fund Scheme*. An amount of **₹1,400 Crore** has been approved under the **Chief Minister Development Fund** to meet capital and infrastructure-related requirements.

Hon'ble Members,

11. Giving priority to the health sector, my Government has allocated **13 per cent** of its total expenditure to health, which is significantly higher than the average health expenditure by other states.

12. To strengthen the health infrastructure, works are underway in 17 hospitals. In the same order, five hospital blocks were inaugurated in September 2025.

13. Following the formation of the new Government in February 2025, the first major decision taken in the health sector was the implementation of the *Ayushman Bharat–Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana*. So far, 6,72,551 Ayushman Cards have been issued, including 2,62,383 *Vay Vandana Yojna Cards* for senior citizens aged above 70 years. Under the scheme, 188 hospitals in Delhi—137 private and 51 government—have been empanelled. Under this, 19,287 patients have received successful treatment to date.

14. Under the PM-ABHIM scheme, **238 Ayushman Arogya Mandirs** are being made operational, which is strengthening primary healthcare services and reducing the burden on tertiary hospitals. To ensure the availability of affordable medicines, **29 Jan Aushadhi**

Kendras are also functioning. In addition, work is underway to establish 11 Integrated Public Health Laboratories and 9 Critical Care Blocks.

15. Under the Digital India initiative, **Hospital Information Management System** has been implemented in 37 hospitals.

16. In the direction of expanding integrated healthcare services, the Delhi Government has approved the implementation of the National AYUSH Mission and the constitution of the **Delhi State AYUSH Society.** By this, holistic development of AYUSH systems of medicine will be ensured. Emergency services have been further strengthened with the addition of 53 new ambulances, taking the total number to 330.

17. Under the Prime Minister’s National Dialysis Programme and the PPP Dialysis Project, **free haemodialysis services** are being provided to economically weaker sections and affordable services to the general public. At present, 300 Machines are operational across 16 Dialysis centres, of which 150 Machines have been installed by the Government within a very short span of time. In the last few months, appointment of **926 Nursing Officers, 141 Paramedical Personnel** and **127 Non-Teaching Specialists** has further strengthened patient care in health institutions. My Government has also enhanced the **stipend for Nursing Interns** from ₹500 per month to **₹13,150 per month.** This step taken by the Government is commendable.

18. In addition, with special emphasis on mental health, Delhi’s first **Brain Health Clinic** has also been inaugurated in Dwarka.

Hon’ble Members,

19. My Government firmly believes that quality education is the fundamental right of every child, not a privilege. Guided by this conviction, **19 per cent of the Budget** for the year 2025–26 has been allocated to the education sector. The allocation reflects Government’s vision of education as a positive investment in the future.

20. To address the problem of arbitrary fee hikes by private schools, the *Delhi School Education (Transparency in Fixation and Regulation of Fees) Act, 2025* has been enacted. This law is a historic step towards preventing education from becoming a commercial enterprise.

21. With the objective of honouring the memory and legacy of the ‘People’s President’, **100 Dr. A. P. J. Abdul Kalam Language Laboratories** are being established in Government schools in Delhi. These laboratories will use state-of-the-art technology and AI to impart instruction in English, Hindi, other Indian languages, as well as foreign languages such as French, German and Spanish.

22. Inspired by the concept of PM SHRI Schools under the **National Education Policy–2020**, **75 CM SHRI Schools** have been launched in Delhi. In these schools, each class will be equipped with Smart Classrooms, Computer Labs, Modern Laboratories, Libraries and other facilities.

23. **Smart classrooms** are being set up in all Government schools for Classes IX to XII. In today's digital age, access to technology is not a luxury but a necessity. Under Chief Minister's Digital Education Scheme, work is underway to provide **free Laptops to 1,200 meritorious students** admitted from Class X to Class XI.

24. To meet modern educational standards prescribed by CBSE, **175 IT Labs** are being established in Government schools, and **each lab will be equipped with 40 Computers.**

25. My Government has taken commendable step by more than **doubling the sports incentive amount** for athletes. Under this initiative, it has been decided to award prize money of **₹7 Crore, ₹5 Crore and ₹3 Crore respectively to Gold, Silver and Bronze medal winners in Olympic and Paralympic Games—the highest in the country.** In addition, sports incentive amount for Asian, Commonwealth and other international and national sporting events have also been **increased by one-and-a-half to three times.** I commend the Government's dedication to sports and sportspersons.

Hon'ble Members,

26. In the Budget for 2025–26, my Government has **doubled the capital expenditure to approximately ₹28,000 Crore.** The objective is not merely structural construction, but to prepare Delhi as a future-ready capital that embodies a balance of speed, convenience and sustainability.

27. Under the Electric Vehicle initiative with the help of Government of India, approximately 3,535 Electric Buses have been inducted, of which about **1,150 DEVI Buses** have already been deployed to strengthen **last-mile connectivity.** Simultaneously, work is underway on a plan to establish 36,000 Electric Charging points.

28. To ensure seamless travel between Buses and Metro, the Government is working on implementing the **National Common Mobility Card (NCMC)**, which will be valid across both modes of transport. This facility will be provided **free of cost** to women in Delhi in the form of a **Pink Card.**

29. To promote public transport, Government has made a provision of approximately ₹3,300 Crore for Metro Phase-IV. Additionally, under the leadership of Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, **Delhi–Meerut Namo Bharat Rail service** has been launched, for which my Government expresses its gratitude to the Hon'ble Prime Minister.

30. In a short span of time, my Government has renovated 150 km of roads; and construction and redevelopment of 400 km of roads will be completed by March 2026. Furthermore, the renovation of 600 km of roads is planned during the year 2026. My Government is resolutely committed to ensure that the remaining 300 km of roads are also fully renovated by the end of the financial year 2026–27.

31. After many years, Government has received central assistance of ₹803 Crore from Ministry of Road Transport and Highways. In addition, work is underway on plans for the development of three major roads in Delhi—M.G. Road, Mathura Road and Rohtak Road—through the National Highways Authority.

32. My Government expresses its heartfelt gratitude to Hon'ble Prime Minister for construction of the Delhi section of the Dwarka Expressway and Urban Extension Road–II. Built at a cost of ₹11,000 crore, these transformative projects will reduce traffic congestion, shorten travel time and strengthen connectivity across the Delhi–NCR region.

33. The long-pending Nand Nagri Flyover has also been completed by my Government within a short period, enabling improved connectivity between several Trans-Yamuna colonies and Delhi and the NCR. Work on the Barapulla Flyover, which had remained stalled for years, has been resumed and after obtaining all necessary approvals, will be completed by May 2026. Similarly, the construction of new flyovers at Modi Mill and Savitri Cinema has also been approved.

34. Waterlogging has been a long-standing problem in Delhi, especially during the monsoon. In this direction, Government has taken proactive and effective measures. Desilting of drains has been carried out on a war footing, with approximately **22 Lakh Metric Tonnes of silt removed till date.** Sewer lines are being cleaned regularly, and Smart Drainage Systems equipped with real-time monitoring are being developed in vulnerable areas to prevent waterlogging.

35. After nearly fifty years, a new **Drainage Master Plan** has been prepared for the entire city of Delhi, which will be implemented in the coming years at an estimated cost of ₹56,000 crore.

36. **All three Criminal Laws** enacted by the Centre have also been implemented in Delhi. Projects have been initiated to improve infrastructure of the Courts and to provide facilities such as family courts, residential buildings, Advocates' chambers, and new Court complexes. Approval is also being granted for construction of a high-security prison complex in Narela. The **e-forensic System** has been implemented, reflecting the Government's priority towards Justice.

37. My government is fully committed to sustainable and holistic development of the people living in slums. Government is renovating dilapidated EWS flats constructed during the previous Government's tenure and is allotting these flats to poor families. In addition, a provision of approximately ₹700 crore has been made for development of basic amenities in these colonies. In these colonies, facilities such as *Ayushman Arogya Mandirs* and *Atal Canteens* are also being provided. In keeping with its firm commitment to social welfare, my Government has launched the *Atal Canteen Scheme*, under which nutritious **meals are being provided at a nominal cost of ₹5.** On the occasion of the **Birth Anniversary of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee, 45 out of the envisaged 100 Atal Canteens have been inaugurated** and the remaining canteens will be launched shortly. I welcome this initiative of the Government led by the Hon'ble Chief Minister, taken to ensure facilities and dignity for poor families.

Hon'ble Members,

38. Owing to years of neglect and pollution, the condition of the Yamuna River has remained deplorable. Upon assuming office, my Government accorded the **highest priority to the cleanliness of the Yamuna.** Work on the rejuvenation of the river is being undertaken simultaneously at multiple levels. New Sewage Treatment Plants (STPs) are being installed and priority is being given to the upgradation of existing STPs. The impact of all these initiatives will become evident in the times to come. The Government is also working on plans to tap and treat all those drains that pollute the Yamuna by installing **decentralized STPs.**

39. An allocation of **₹9,000 Crore** has been made to the Delhi Jal Board to strengthen the water supply system. With the objective of augmenting water supply, the **capacity of Water Treatment Plants is being enhanced.** Government is also promoting the recycling of wastewater and is making sustained efforts to rejuvenate water bodies such as the Najafgarh drain and the Yamuna floodplains. Work has also commenced on **installing bio-gas plants** to prevent cattle dung from entering drains, alongside systematic desilting of drains.

40. In November 2025, the Government took an important and people-centric decision by removing the restrictions under which properties **'booked'** by the Municipal Corporation of Delhi for unauthorised construction were being denied electricity connections. Following this decision, power distribution companies can no longer refuse or disrupt electricity supply solely on the ground that a property is included in the MCD's 'booked' list. This policy change has benefited more than 1.25 lakh families in Delhi whose homes were earlier deprived of electricity due to these restrictions and who can now lawfully obtain electricity connections.

Hon'ble Members,

41. To implement the long-pending **PM SWAMITVA Scheme** in *Delhi*, *the Delhi Abadi Deh Survey and Record Operations Rules, 2025* have been notified. By this, for the first time, legal property rights upon Lal Dora Abadi areas in rural regions will be conferred. I congratulate my Government on this historical work.

42. To make administration more effective and to ensure easier access to citizen services, the Delhi Government, with effect from **Good Governance Day on 25 December 2025**, has reorganised its 11 Revenue Districts and created **13 new Districts**, so as to align boundaries with MCD zones, NDMC and the Delhi Cantt. Administrative reform, undertaken in public interest by the Government, deserves commendation.

43. In addition, the Government has approved establishment of **Mini Secretariats** in all 13 districts. These multi-departmental centres will provide all services under one roof and will function as a single point of contact for citizens.

44. As part of an important initiative, through **weekly public grievance hearings**, Hon'ble Chief Minister, District Magistrates and Sub-Divisional Magistrates are directly listening to Citizens' issues and issuing necessary directions for their prompt resolution.

45. With the objectives of timely redressal of public grievances, effective service delivery, wide dissemination of information and receipt of citizens' suggestions and ideas, **Delhi Mitra App** has been conceptualised. Work is also underway on the development of a **web portal for grievance redressal management.**

46. Alongside this, 85 youth have been engaged under the **Viksit Delhi Internship Programme.** To strengthen the tourism sector and promote heritage conservation, Government has also approved the **Tourism and Heritage Fellowship Programme.**

47. **Anganwadi Centres** have been co-located in government buildings and mapped with Government schools. 502 Anganwadi-cum-Crèche **'Palna'** centres have also been started. With the objective of increasing women's participation in the workforce, the Government has removed the restrictions and permitted women to work in night shifts in Delhi.

48. For the welfare of marginalized sections of society, Savitribai Phule Senior Citizen Home in Paschim Vihar, Atal Drishti Home in Timarpur and Atal Asha Home in Narela have been established and opened for public use.

49. Furthermore, during the period of GRAP, when restrictions were imposed on construction activities in Delhi-NCR, Government safeguarded the interests of construction workers by providing financial assistance to building and other construction workers. Under this

initiative, an **ex-gratia amount of ₹10,000** was disbursed to each eligible worker to support their livelihood during difficult times.

50. My Government has revitalised the **Delhi Village Development Board**, under which work will be undertaken on **776 development projects** with an estimated cost of approximately **₹1,715 crore.**

51. Approval has also been granted to provide **monthly assistance of ₹6,000**, in addition to other pensions, to persons with disabilities requiring extensive care. This will help meet the costs of caregiving arrangements, treatment, and assistive devices.

52. Government has approved a new policy to provide compassionate appointment in government service to dependents of the **victims of the 1984 anti-Sikh riots** and 56 beneficiaries have been provided employment till date. In addition, one-time relief has been extended to **Jammu and Kashmir migrants** residing in Delhi by removing the income eligibility condition.

53. Being the national capital and with the objective of showcasing unity and cultural diversity, Government has begun celebrating the **'Foundation Days'** of all States and Union Territories of India. Additionally, Tourism Department has been organising important days and festivals such as International Yoga Day, Aam Mahotsav, and Teej Mahotsav. In these programmes, participation of general public has been extremely encouraging and commendable.

54. For the first time, financial assistance has been provided directly to **Kanwar Committees through a Single Window System via Direct Benefit Transfer.** As a result, the Kanwar Yatra organised this year was highly successful. With the objective of preserving and promoting cultural and religious traditions and to reduce the financial burden on organising committees, the Government has provided up to **1200 units of free electricity to Ramlila and Durga Puja Committees.** This year, the festivals of **Deepotsav and Chhath Mahaparv** were organised in an exemplary manner at the Yamuna ghats, witnessing participation by lakhs of people. Similarly, the **350th Martyrdom Day of Guru Tegh Bahadur Ji and Veer Bal Diwas** were also commemorated.

55. My Government firmly believes that respecting all cultural and religious traditions while providing better facilities to citizens is the hallmark of inclusive and sensitive governance.

Hon'ble Members,

56. Air pollution is one of the most serious challenges facing our city today. Clean air is not a privilege, but a fundamental right of every citizen.

57. My Government is fully committed to **pollution control.** Instead of limiting itself, as in previous years, to only seasonal measures, the Government launched a comprehensive, year-round and time-bound **Air Pollution Mitigation Plan** in June 2025. This plan focuses on prevention, use of modern technology, strict enforcement and public participation, with coordinated efforts involving all departments, local bodies and the agencies of NCR.

58. To strengthen air quality monitoring, **06 new Air Quality Monitoring Stations** are being established. This will ensure the availability of real-time data, transparency and accountability. By adopting effective measures, the Development Department reduced **incidents of stubble burning within Delhi to zero** during the winter of 2025.

59. In addition, work is being expedited to establish **03 Automated Testing Stations (ATS)** at Nand Nagri, Burari and Tehkhand for technology-based fitness testing of approximately 2.5 lakh commercial vehicles every year.

60. When pollution levels rose in recent weeks, Government immediately took ground-level actions. More than 1800 inspection teams have been deployed, operating round the clock. Under **'Ek Ped Maa Ke Naam'** campaign, green cover is being expanded. Within just ten months, 1450 Electric Buses have been inducted, significantly strengthening non-polluting public transport. Inter-State EV Bus services have also been introduced on several routes. For dust control, mechanical road sweepers in double shifts, water sprinkling and extensive use of anti-smog guns are being deployed. To strengthen sanitation systems and control pollution, a decision has been taken to provide financial assistance of **₹2,300 Crore** to Municipal Corporation of Delhi for **70 MRSMs** and **1,000 litter picker machines** over a period of ten years.

61. To prevent incidents of open burning during the winter season, **3000 Electric Heaters** have been distributed free of cost to RWAs and uninterrupted 24×7 electricity supply has been ensured across the city.

62. My Government has provided an additional grant of ₹500 Crore to Municipal Corporation of Delhi this year and will further provide an annual grant of ₹300 Crore in the coming years, which will accelerate waste management and environmental protection efforts.

63. Under the PPP model, Government is working towards establishing Delhi's first **Integrated e-waste Eco Park** at Holambi Kalan. Under this initiative more than 51,000 tonnes of e-waste will be scientifically treated every year.

64. Government is clearing Ghazipur, Bhalswa and Okhla landfill sites through biomining and waste-to-energy technologies. With the objective of making Delhi a garbage-free city, the Government aims to reduce the mountains of waste by 2027 through the use of trommel machines under the PPP model.

65. Vehicular pollution control is also a key focus area of the Government. Through Electric Buses, last-mile connectivity, e-mobility and a rapidly expanding EV Charging network, Delhi's Public Transport System is being continuously strengthened. By December 2026, under the revised EV Policy, more than 7,700 clean-fuel buses will be added. To control traffic congestion and the emissions arising from it, Government has also deployed 600 additional personnel.

66. For systematic management of Construction and Demolition (C&D) waste, which currently amounts to approximately 6,000 tonnes per day, 04 processing plants are already operational, and a new plant with a capacity of 1,000 TPD will be commissioned by December 2026. In addition, a circular economy is being promoted through the mandatory reuse of processed waste in government projects.

67. Road dust control has been accorded special priority. A comprehensive road redevelopment and greening plan covering all categories of roads has been prepared, which will be fully implemented before the next winter season, supported by large-scale mechanised cleaning and water sprinkling systems.

68. Industrial pollution control has been strengthened through regular inspections, real-time monitoring and strict action against illegal units. A new industrial policy is being formulated to permit only clean industries.

69. To further reinforce these efforts, several initiatives have been undertaken. In these, mandatory installation of anti-smog systems for high-rise commercial buildings, installation of Mist Spray Systems at pollution hotspots and strict enforcement of the **'No PUCC, No Fuel'** policy are included. Additionally, **more than 650 Mist Spray Systems** have already been installed on roads by PWD, DDA, NDMC and DMRC.

70. Clean air is a shared responsibility. Government's efforts can succeed only with active cooperation of citizens. Public awareness and participation are being continuously strengthened through schools, RWAs and community organisations. At the same time, in line with the commitment to make Delhi a green city, there is a target to plant more trees. Over the next four years, approximately 35 lakh trees and 63 lakh shrubs will be planted. Along with this, plantation of indigenous trees such as Neem, Mango, Banyan, and Peepal is being undertaken. **To promote Solarisation**, Government has increased the State subsidy under the **PM Surya Ghar Scheme from ₹2,000 per Kilowatt to ₹10,000 per Kilowatt.**

Hon'ble Members,

71. Although the Government has achieved several notable accomplishments, many challenges still remain to be addressed. Government is confronting all these challenges with

unwavering resolve, commitment and transparency, moving forward with the conviction that through collective effort, these obstacles can be transformed into opportunities.

72. I have placed before you a brief outline of my Government's major development-oriented policies and public welfare schemes. I do not hope, but firmly believe, that all Hon'ble Members will extend their cooperation to the Government, place public interest above all else, participate in fulfilling public aspirations and uphold the dignity of this august House.

Hon'ble Members,

73. It is a constitutional responsibility of the public representatives to provide positive leadership and meaningful direction to the aspirations and expectations of the citizens they represent. Your role in shaping public policies and guiding the processes of governance is of paramount importance. By doing so, you will be able to transform the aspirations of the people into tangible outcomes and inclusive development.

74. It is my hope and expectation that the proceedings of this august House will be conducted with maturity, wisdom, cooperation and the spirit of healthy democratic deliberation. I have full confidence that, inspired by selfless service and an unwavering commitment to public welfare, the deliberations of this House will make a meaningful contribution to overall development and progress of Delhi.

75. With these words, I extend my New Year greetings to you all and wish you good health, happiness and prosperity.

Jai Hind!

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जन्मदिन की बधाई। माननीय सदस्यगण । आज माननीय मुख्य सचिव तक श्री अभय वर्मा जी का जन्मदिन है। मैं इस अवसर पर उनको अपनी ओर से तथा पूरे सदन की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ तथा कामना करता हूँ कि वह अपने व्यक्तिगत तथा राजनीतिक जीवन में नई ऊंचाइयां प्राप्त करें। तो अभय जी, आज कुछ आपकी तरफ से।

----व्यवधान ----

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: लंच के दौरान अभय जी का जन्मदिन सेलिब्रेट किया जाएगा। अब जैसे ये चाहेंगे वैसे होगा।

----व्यवधान ----

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: करनैल सिंह जी का, करनैल सिंह जी को भी बहुत-बहुत सदन की ओर से बधाई। अब मैं माननीय मंत्री, श्री परवेश वर्मा जी से अनुरोध करूंगा की वो अपना विषय रखें।

श्री प्रवेश साहिब सिंह(माननीय लोक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष जी आपकी अनुमति हो तो मैं सदन के सामने दो प्रस्ताव रखना चाहता हूँ

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: जी

श्री प्रवेश साहिब सिंह(माननीय लोक निर्माण मंत्री): पहला प्रस्ताव है कि काफी सम्मानित सदस्यों द्वारा ये हमको निवेदन मिला कि और मैं ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ कि आगामी तीन दिनों के लिए यानि ये पूरा विधानसभा सत्र जो की दोपहर 2:00 बजे से पहले होता था हम उसको प्रातः 11:00 बजे से शुरू किया जाए ताकि सारे कार्यों को व चर्चाओं को पूरा समय मिल सके।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: कल सदन की बैठक11:00 बजे से प्रारंभ होगी और बाकी का सदन का कार्यकाल सुबह 11:00 बजे से कार्यवाही होगी।

<u>सदस्यों के निलंबन सबंधी प्रस्ताव</u>

श्री प्रवेश साहिब सिंह(माननीय लोक निर्माण मंत्री): अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से सदन के सामने एक निंदा प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि जैसे हमने देखा उप राज्यपाल जी के अभिभाषण के दौरान उपराज्यपाल जी की जो अवमानना की गई और जो विपक्ष के द्वारा गैर जिम्मेदाराना बर्ताव यहाँ पर हमने देखा। तो मैं आप के माध्यम से सदन के सामने प्रस्ताव लाना चाहता हूँ कि जिन सदस्यों ने ये विघ्न डाला और उसकी शुरुआत की ऐसे सदस्य श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोम दत्त व श्री जरनैल सिंह जी को आगामी तीन दिनों के लिए यानि की छः, सात और आठ तारीख के लिए पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जाए।

श्री विजेन्द्र गुप्ता, माननीय अध्यक्ष: यह प्रस्ताव सदन के समक्ष है। माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह, श्री संजीव झा, श्री कुलदीप कुमार, श्री सोम दत्त, मैं एक बार फिर से जिन्होंने माननीय उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण में सदन की अवमानना की। माननीय उपराज्यपाल महोदय की अवमानना की और एक संवैधानिक व्यवस्था पर बिना किसी कारण के यहाँ पर हंगामा किया।

उसी समय इन चारों सदस्यों को नामित किया गया था और उनको कार्यवाही से बाहर जाने के लिए कहा गया था और फिर मार्शल्स की मदद से उनको बाहर भेजा गया। अब यह प्रस्ताव सदन के समक्ष है कि जरनैल सिंह, माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह, माननीय सदस्य श्री संजीव झा, माननीय सदस्य श्री कुलदीप कुमार और माननीय सदस्य श्री सोम दत्त जी को सदन की कार्यवाही से 3 दिन के लिए निष्कासित किया जाता है।

(सदस्यों द्वारा मेज थपथपाकर सहमति दी गई।)

अब सदन की कार्यवाही मंगलवार 6 जनवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(सदन की कार्यवाही मंगलवार 6 जनवरी, 2026 को प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)